

संसदीय बैठकों और POCSO अधिनियम, 2012 पर वधियक

प्रलिस के लयि:

[नजि सदस्य वधियक](#), [राज्यसभा](#), [लोकसभा](#), [अनुच्छेद 85](#), [अनुच्छेद 174](#), [राष्ट्रीय अपराध रकिरड बयुरो](#)

मेन्स के लयि:

संसदीय कार्यप्रणाली में सुधार, बालकों से संबधति मुद्दे, POCSO और बाल कल्याण कानूनों का कार्यान्वयन

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

न्यूनतम संसदीय बैठकों को अनविर्य करने और [लैंगकि अपराधों से बालकों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#) में संशोधन करने पर ध्यान केंद्रति करते हुए, [नजि सदस्यों के वधियक राज्यसभा](#) में प्रस्तुत कयि गए।

संसदीय बैठकों से संबधति वधियक क्या है?

- **उद्देश्य:** प्रतविर्य न्यूनतम 100-120 संसदीय बैठकों अनविर्य करने के लयि [राज्यसभा](#) में दो वधियक प्रस्तावति कयि गए, जसिमें व्यवधानों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई उत्पादकता बढ़ाने और [सरकारी जवाबदेही में सुधार के लयि वसितारति सत्रों](#) से की जाएगी।
 - वर्ष 1955 में लोकसभा की [सामान्य प्रयोजन समति](#) ने एक नशिचति संसदीय कैलेंडर के वचिर पर वचिर कयि, जबकविर्य 2002 के राष्ट्रीय संवैधानकि समीक्षा आयोग ने राज्य सभा के लयि न्यूनतम 100 दनि और लोकसभा के लयि 120 दनि की बैठकों की सफिरशि की।
- संसदीय बैठकों का वर्तमान परदृश्य: [प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू](#) के अधीन [पहली लोकसभा \(1952-1957\)](#) में प्रतविर्य औसतन 135 बैठकों होती थी, जबकि [17वीं लोकसभा \(2019-2024\)](#) में प्रतविर्य केवल 55 दनि बैठकों हुईं, जो इतिहास में सबसे कम है।
- संवैधानकि प्रावधान: संवैधान में सत्रों या बैठकों के दनिों की नशिचति संख्या का प्रावधान नहीं है।
 - हालाँकि, [अनुच्छेद 85 \(संसद\)](#) के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदन को बुलाता है, तथा यह सुनिश्चति करता है कि दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतराल न हो। राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान या वधितन भी कर सकता है।
 - [अनुच्छेद 174 \(राज्य वधिनमंडल\)](#) के अनुसार राज्यपाल को वधिनसभा को बुलाने, स्थगति करने और भंग करने की शक्ति प्राप्त है, जसिसे सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतर सुनिश्चति होता है।

नजि सदस्य वधियक क्या है?

पढ़ने के लयि यहाँ क्लकि कीजयि: [नजि सदस्य वधियक](#)

POCSO अधिनियम, 2012 में संशोधन संबधी वधियक क्या है?

- **उद्देश्य:** लैंगकि अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) वधियक, 2024 का उद्देश्य POCSO अधिनियम को **अधिक पीडति-केंद्रति बनाना** और इसके कार्यान्वयन में सुधार करना है।
- **वधियक के प्रावधान:** **POCSO (संशोधन) वधियक, 2024** में 24 घंटे की रपिरटगि नियम को अनविर्य कयि गया है, जसिके तहत पुलसि या वशिष कशिोर पुलसि इकाई को बच्चे को **बाल कल्याण समति** के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और मामले की रपिरट **वशिष न्यायालय** (या सत्र न्यायालय, यदि उपलब्ध न हो) को देनी होगी।

- यह समय पर मुआवजा और संरक्षित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करके पीड़ितों के समर्थन को मज़बूत करता है।
- इसमें बेहतर कार्यान्वयन के लिये पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों और बाल देखभाल कर्मियों सहित हतिधारकों के प्रशिक्षण को बढ़ाने का आह्वान किया गया है।
- संशोधन की आवश्यकता: **NCRB के आँकड़ों** के अनुसार, वर्ष 2017 से POCSO मामलों में 94% की वृद्धि हुई है, मई 2024 तक 2 लाख से अधिक पंजीकृत मामले थे।
- संरक्षित मुआवजा प्रक्रियाओं की कमी के कारण पीड़ितों को लंबे अंतराल का सामना करना पड़ता है।
 - POCSO मामलों के लिये प्रशिक्षित विशेष लोक अभियोजकों की कमी है, जिससे बाल यौन शोषण मामलों से नपिटने में संवेदनशीलता और दक्षता प्रभावित होती है।
- डर, कलंक या जागरूकता की कमी के कारण कई मामले रिपोर्ट नहीं किये जाते या वलिंब से दर्ज किये जाते हैं।
- POCSO अधिनियम, 2012 में एक प्रमुख कमी पीड़ितों के लिये "सहायक व्यक्तियों" की कमी है, 96% मामलों में आवश्यक सहायता का अभाव है।
 - ये सहायक व्यक्ति, चाहे वे व्यक्ति हों या संगठन, पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा उनकी भलाई सुनिश्चित करते हैं।
 - सहमति से यौन क्रियाकलाप में शामिल 16-18 वर्ष की आयु के नाबालगों पर POCSO के तहत आरोप लगाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक हरिसत में रहना पड़ सकता है और ज़मानत से इनकार किया जा सकता है।
- इसके अलावा, **POCSO न्यायालयों की अपर्याप्त नयुक्तों से न्याय में और वलिंब होता है, क्योंकि सभी ज़िलों में ये विशेष न्यायालय नहीं हैं।**

POCSO अधिनियम, 2012

- POCSO अधिनियम, 2012 बालकों के यौन शोषण और दुरव्यवहार से नपिटने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है।
- POCSO अधिनियम यह मानता है कि बालक और बालिका दोनों ही यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं, और पीड़ित के लिये की परवाह किये बिना अपराध दंडनीय है। यह 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है।
- इसमें कहा गया है कि पीड़ित बालकों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये, पीड़ित के नाम, पते या परिवार के विवरण के बारे में मीडिया में कोई खुलासा नहीं किया जाएगा।
- अधिनियम में यह प्रावधान है कि बाल दुरव्यवहार के बारे में जानकारी या संदेह वाले व्यक्तियों को इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को देनी होगी।

????? ???? ????:

प्रश्न: भारत की वधायी जवाबदेही के संदर्भ में संसदीय बैठकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये।

प्रश्न: POCSO अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं, समाधान के उपाय सुझाइए?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????? ???? ????:

प्रश्न: भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा नमिनलखिति में से क्या परकिल्पति कयिा गया है? (2017)

1. मानव तस्करी और बलात् शर्म पर प्रतर्बिध
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हतियों का संरक्षण
4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नयिोजन का प्रतर्षिध

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

????? ????:

प्रश्न. राष्ट्रिय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण करते हुए इसके कार्यान्वयन की स्थितिपर परकाश डालयिे। (2016)

